राजीविका महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा सामाजिक बदलाव ला रही हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बाँसवाड़ा के चुड़ादा गाँव में चौपाल कार्यक्रम में राजीविका महिलाओं से संवाद किया

बांसवाड़ा/जयपुर, 20 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राजीविका महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल है। इसके माध्यम से गांव

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डूंगरपुर और बाँसवाड़ा की महिलाओं ने लखपति दीदी योजना में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने आव्हान किया है कि महिलाएं स्वयं आग बढ़ें व राजीविका के समूहों से औरों को भी जोड़ें।**

की महिलाएं लाखों - करोड़ों रुपये के करोबार से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। ये न केवल रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी ला रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व की दिशा में "नारी शक्ति वंदन" अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण की शुरूआत की। इस अधिनियम को और सशक्त करने की प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहल की, लेकिन विपक्ष ने राजनीति के चलते इस बिल को संसद में पारित नहीं होने दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। यह योजना महिलाओं की आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन गई है। प्रदेश की 22 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से लगभग 17 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी महिलाओं ने इस योजना में बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। उन्होंने आ ान किया कि महिलाएं स्वयं भी आगे बढ़ें और राजीविका के समूहों से औरों को भी जोड़ें। वे छोटी पूंजी से अपने बड़े सपनों को साकार करें।

मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को चैक भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने वन धन मैनेजर विधिका के आग्रह पर बांसवाड़ा में राजीविका बहनों के लिए सीएलएफ कार्यशाला बनवाने एवं क्लस्टर मैनेजर धर्मिष्ठा पण्ड्या के अनुरोध पर उत्पादों की पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। इससे पहले, स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी अंचल के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आदिवासी बंडी (जैकेट) एवं तीर-कमान भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया।

कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, विधायक कैलाशचन्द्र मीणा, शंकरलाल डेचा सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नारी शक्ति व ग्रामीण मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर आदिवासी बंडी (जैकेट) एवं तीर-कमान भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया।

प्र.मंत्री मोदी ने मेलॉनी को दी "मेलॉडी"

नई दिल्ली, 20 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने इटली दौरे पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलॉनी को खास तोहफे के रूप में मेलॉडी टॉफी गिफ्ट की। मेलोनी ने इसका वीडियो एक्स पर शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मेलोनी ने स्वयं अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी मेलॉनी को गिफ्ट देते दिखाई दे रहे हैं और बदले में

- **इन्टरनैट पर वीडियो वायरल, इटली की प्र.मंत्री जॉर्जिया मेलॉनी ने मोदी का आभार जताया।**

मेलॉनी लिखती हैं- इस उपहार के लिए धन्यवाद। 'मेलोडी' शब्द इटली की प्रधानमंत्री की ओर से दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों को रेखांकित करते हुए बनाया गया है। इसमें उन्होंने अपने और प्रधानमंत्री मोदी के नाम को जोड़ा है। इससे पहले वे तीन बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए हैशटेग 'मेलॉडी' का प्रयोग कर चुकी हैं।

दोबारा होने वाली एसआई परीक्षा में आवेदन स्वीकार करें- हाई कोर्ट

याचिकाकर्ता ने 2024 भर्ती के लिए आवेदन किया था, पर दोनों परीक्षाएं नहीं दे पाया था

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के कारण रद्द की गई एसआई भर्ती: 2021 में आवेदन कर परीक्षा नहीं देने वालों को आगामी सितंबर माह में दोबारा होने वाली एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में शामिल करने के लिए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मधुसूदन शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने भर्ती की दोनों ही परीक्षाएं नहीं दीं। उन्हें एसआई 2021 की दोबारा होने वाली परीक्षा में यह कहते हुए शामिल नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा नहीं दी थी। इसमें पूर्व में दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है।

- **याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था।**

याचिका में कहा गया कि जब पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द हो चुकी है तो अब आगामी परीक्षा में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं कहा है कि जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लिया था, उन्हें ही वापस होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करें। पूर्व में जब ईओ-आरओ भर्ती की परीक्षा रद्द हुई थीं, तब उनमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। इसलिए सितंबर 2021 में होने वाली एसआई 2021 की पुन: परीक्षा में उन्हें भी शामिल किया जाए।

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए ही पुन: परीक्षा आयोजित करने को कहा था। इसके अलावा, आवेदन करने के बाद करीब चार लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने को कहा है। गौरतलब है कि एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के चलते हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुन: परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है।

दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का मिलाजुला असर दिखा

यह हड़ताल ऑनलाइन दवा कंपनियों को बंद करने के लिए की गई थी

नई दिल्ली, 20 मई। देश में ऑनलाइन फार्मेसियों और भारी छूट के खिलाफ ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आ ान पर बुधवार को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर मिला-जुला रहा।

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ऑनलाइन दवा कंपनियों (फार्मेसी) के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। एआईओसीडी का कहना है कि वह 12.4 लाख दवा विक्रेताओं (केमिस्ट, फार्मासिस्ट) और वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में कुछ संगठित फ़ार्मेसी चेन की दुकानें

- **ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आव्हान पर हड़ताल आयोजित की गई थी।**

खुली हुई थीं। देशव्यापी केमिस्ट, फार्मासिस्ट और दवा वितरकों हड़ताल के आ ान के बारे में पूछे जाने पर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हम इस हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं।

एआईओसीडी के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि दवा की सभी दुकानें बंद हैं। हमें हमारी राज्य इकाइयों से जानकारी मिली है कि सभी देशव्यापी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। हमने अस्पतालों के भीतर संचालित 'नर्सिंग होम फार्मेसियों' पर कोई दबाव नहीं बनाया है। सिंघल ने दोहराया कि एआईओसीडी जीएसआर 817 और जीएसआर 220 अधिसूचनाओं के खिलाफ विरोध कर रहा है, क्योंकि ये प्रभावी रूप से ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को नियमित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे बिना उचित भौतिक सत्यापन के दवाओं की बिक्री हो रही है। कॉर्पोरेट समर्थित ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट दे रही हैं, जिससे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि एआईओसीडी अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए एक-दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के बाद आगे की रणनीति पर विचार करेगा।

पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य शरद पवार ने पुणे स्थित लक्ष्मणराव गुट्टे ग्रामीण विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित पूर्व पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कही।

ब्रिक्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने कहा कि शी, पुतिन से भारत में दूसरी बार मुलाकात करेंगे।

दोनों की बैठक बीजिंग में हुई थी, लेकिन इसमें रूस और चीन के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विवरण पर कोई समझौता नहीं हुआ।

फ़र्ज़ी टेलिग्राम चैनलों पर कार्यवाही होगी

नई दिल्ली, 20 मई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) पुनर्परीक्षा की निष्पक्ष और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को केन्द्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में परीक्षा के दौरान कड़ी सतर्कता और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया।

शिक्षा मंत्री ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार, विशेष रूप से टेलीग्राम चैनलों और गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से फैलाए जा रहे भ्रामक दावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

अमेरिकी संसद में ट्रंप पर अंकुश लगाने वाला प्रस्ताव पारित हुआ

इसका लक्ष्य ट्रंप की सैन्य शक्तियां सीमित करना और उन्हें ईरान युद्ध से हटने के लिए मजबूर करना है

वॉशिंगटन, 20 मई। अमेरिकी संसद में मंगलवार को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। इसका उद्देश्य ट्रंप को ईरान युद्ध से पीछे हटने के लिए मजबूर करना है।

चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी राष्ट्रपति की इच्छा के खिलाफ जाकर विपक्षी डेमोक्रेटिक सदस्यों का साथ दिया। हालांकि, तीन रिपब्लिकन सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर से उभरते असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। फरवरी के अंत में ट्रंप द्वारा ईरान पर हमला करने का आदेश दिए जाने के बाद से डेमोक्रेट सांसद बार-बार युद्ध अधिकार प्रस्तावों पर मतदान करवा रहे हैं। इन प्रस्तावों के तहत ट्रंप को या तो युद्ध के लिए कांग्रेस की सहमति लेनी होगी या फिर सैनिकों को वापस बुलाना होगा। अब तक रिपब्लिकन सांसद इन प्रस्तावों को खारिज करने के लिए पर्याप्त वोट

- **डैमोक्रेट्स के अलावा तीन रिपब्लिक सांसदों ने भी इसका समर्थन किया, यह संकेत है कि रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है।**

जुटाने में सफल रहे थे, लेकिन लुइसियाना के सीनेटर बिल कैसिडी ने अपनी राय बदली और विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक वोट दिया। कैसिडी हाल ही में हुए प्राइमरी चुनाव में हार गए थे, जहां ट्रंप ने उनके प्रतिद्वंद्वी का समर्थन किया था।

यह विधेयक 'वॉर पॉवर्स एक्ट' के तहत, राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा है, जो 47 के मुकाबले 50 मतों से पारित हो गया। इस प्रक्रिया से यह बात सामने आई कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी कुछ सांसद ईरान के साथ युद्ध रोकने के पक्ष में हैं। इस विधेयक पर अंतिम मंजूरी के लिए भी मतदान होगा, हालांकि अभी यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि उस पर मतदान कब होगा।

अगर सीनेट में यह प्रस्ताव पारित भी हो जाता है, तो इसे रिपब्लिकन बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) से भी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।

यह वोट विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है जो कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि संसद के पास होना चाहिए। अमेरिकी संविधान में भी यही व्यवस्था दी गई है।

दिल्ली एनसीआर में 26 मई तक ऑरेंज एलर्ट

नई दिल्ली, 20 मई। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है और इस हफ्ते राहत की उम्मीद बहुत कम है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और तेज सतही हवाएं चलेंगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 से 26 मई तक राजधानी और आसपास के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि इस दौरान अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और दिन में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी, जो कभी-कभी झोंकों के साथ 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं।

- **मौसम विभाग ने तापमान 47 डिग्री तक जाने की चेतावनी दी।**

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लू की स्थिति स्वास्थ्य के लिए मध्यम स्तर का जोखिम पैदा कर सकती है।

एसओजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया गया था। एसओजी के अनुसार, आरोपी संदीप सैनी झुंझुनू जिले के बबाई क्षेत्र स्थित मामराज की ढाणी का निवासी है और वर्तमान में जेवीवीएनएल सांगानेर में टेक्निकल हेल्पर के पद पर कार्यरत था।

एसओजी ने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने वाले नेटवर्क, संभावित सरकारी अधिकारियों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

मेघालय में 12 देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरु

शिलांग, 20 मई। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में "प्रगति 2026" का मंगलवार से औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं।

भारतीय सेना ने सभी विदेशी सैन्य दलों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य का परिचायक रहा। 'प्रगति' का पूरा नाम पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज़ फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन है। यह अभ्यास समानता, मित्रता और पारस्परिक सम्मान की भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

- **सभी 12 देशों की सैन्य टुकड़ी मेघालय पहुंच गई हैं।**

क्या प.बंगाल फिर से भारत का इकोनॉमिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करोड़ों के निवेश की घोषणा की थी, जिसे शुरु करने वाले और कोई नहीं, बल्कि बंगाल के चहेते सितारे सौरव गांगुली थे। कहने की जरूरत नहीं कि वह बड़ा निवेश आज तक जमीन पर नहीं उतर पाया।

बहरहाल, बंगाल की इस चौंका देने वाली आर्थिक गिरावट को कुछ गंभीर प्रयासों से शानदार पुनर्जीवन में बदला जा सकता है।

राज्य के किसी भी आर्थिक विकास की पहली शर्त पर्याप्त बिजली उपलब्ध होना है। राज्य ने वर्षों तक गंभीर बिजली संकट झेला। अब स्थिति इसलिए आरामदायक है, क्योंकि भारी उद्योग बंद हो चुके हैं और मैनुफैक्चरिंग उद्योग लगभग समाप्त हो चुका है। हाल ही में एक बड़ी बिस्कुट फैक्ट्री भी बंद हो गई, कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल के कुछ दबंग नेताओं की अनुचित मांगों के कारण।

बिजली परियोजनाओं को पूरा होने में बहुत लंबा समय लगता है। नई सरकार को नई बिजली परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर काम करना चाहिए। इनमें कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी शामिल होने चाहिए। साथ ही दीर्घकालिक योजना में राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना भी देखी जानी चाहिए। वर्षों पहले ऐसी परियोजना शुरू करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी।

कलकत्ता कभी देश का एक प्रमुख वित्तीय केन्द्र था। यह अब भूला-बिसरा इतिहास बन चुका है। मुगल साम्राज्य के समय और फिर अंग्रेजों के भारत में पैर जमाने के दौर में, दुनिया का सबसे बड़ा और सम्मानित बैंकिंग घराना बंगाल में स्थित था। मुर्शिदाबाद स्थित जगत सेठ का घराना मुगल बादशाहों का बैंकर था।

अपने अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के शाही परिवार के खर्चों के लिए बंगाल से मिलने वाला राजस्व ही मुख्य सहारा था। अपने स्वर्णकाल में जगत सेठ के घराने की "हुण्डियाँ" मिस्त्र से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक वैध भुगतान माध्यम की तरह स्वीकार की जाती थीं।

ब्रिटिश साम्राज्य केवल अंग्रेजों ने नहीं बनाया था। उसे जगत सेठ घराने की आर्थिक शक्ति का सहारा मिला था। यह बैंकिंग घराना तब टूट गया, जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के लिए "जगत सेठ घराने" से लिए गए भारी-भरकम कर्ज चुकाने से साफ इनकार कर दिया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले कलकत्ता बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का बड़ा केन्द्र था। यहां एक सक्रिय स्टॉक एक्सचेंज भी था। राष्ट्रीयकरण के बाद कलकत्ता देश के तीन बड़े बैंकों - यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और इलाहाबाद बैंक - का मुख्यालय बना।

इनमें से दो बैंकों का हाल ही में विलय कर दिया गया, ठीक उसी समय, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं। वाम मोर्चा सरकार की तरह, जो पैंतीस वर्षों तक केन्द्र सरकार पर बंगाल की उपेक्षा और शोषण का आरोप लगाती रही, ममता बनर्जी भी लगातार कहती रहीं कि केन्द्र सरकार उन्हें कोई भी सहयोग नहीं दे रही, खास तौर पर उन्हें पैसों का निर्बाध प्रवाह नहीं मिल पा रहा है।

लेकिन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यू.बी.आई.) और इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व समाप्त करने के केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के खिलाफ फैसले के किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। किसी बैंक के खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठी। किसी बैंक का मुख्यालय होने से उस क्षेत्र को आर्थिक रुप से मजबूती मिलती है और आसपास के इलाके को आर्थिक संबल प्राप्त होता है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां और उच्च स्तरीय बैंकिंग प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं। लेकिन राज्य की बैंकिंग पूंजी समाप्त होने पर किसी ने विरोध नहीं किया।

पिछले कुछ सालों में कई नए बैंक सामने आए हैं। वामपंथियों के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल बीमार उद्योगों की राजधानी बन गया था। इसलिए केन्द्र ने इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया (आईआरबीआई) की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। बाद में उसे बंद कर दिया गया। यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ निजी बैंक भी सफलतापूर्वक चल रहे थे। पीयरलेस देश की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक थी।

नई सरकार को इन बैंकों के मुख्यालय वापस कलकत्ता लाने की मांग करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो इलाहाबाद बैंक को अलग इकाई बनाकर उसकी पूंजी मजबूत की जा सकती है। यदि यह संभव न हो, तो विलय किए गए बैंक का मुख्यालय ही कलकत्ता स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

कलकत्ता के स्थानीय पूंजी बाजार को फिर से जीवित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विशेष रूप से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों पर खुले मन से विचार होना चाहिए।

आज बंगाल की आर्थिक और औद्योगिक छवि बेहद खराब हो चुकी है। कोई भी यहां आकर अपना पैसा जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए इसकी छवि सुधारने के लिए गंभीर प्रयास जरूरी हैं।

एक मेहमाननवाज़ और भरोसेमंद स्थान की छवि वापस पाने की कुंजी कलकत्ता की स्थिति सुधारने में है। पहली नजर में शहर की तस्वीर बेहद खराब दिखती है - जर्जर इमारतें, फुटपाथों और सड़कों पर फैले हॉकर, गंदगी और बदहाल इलाके। यहां उम्मीद की कोई किरण दिखना मुश्किल है। फिर भी इस शहर के पास अपार प्राकृतिक और अनोखे संसाधन हैं। एक तरह से, अपने थका देने वाले और ज़ोरदार चुनाव अभियान के बीच भी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस शहर की छवि को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के संकेत दिए थे। सुबह सात बजे उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हावड़ा ब्रिज की पृष्ठभूमि में नौका विहार का आनंद लिया।

इस बात से तत्कालीन सर्वोच्च शासक ममता बनर्जी काफी भड़क उठी थीं, और उन्होंने प्रधानमंत्री को "राजनीतिक पर्यटक" तक कह डाला।

जरा ठहरकर सोचिए। क्या भारत के जीवन में गंगा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है? ऐसी चीज जो भारत की आत्मा, उसकी विविधता और उसके विचार को पूरी तरह दर्शाती हो।

लेकिन बंगाल ने अपनी सुस्ती में कभी गंगा की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सोचिए, बंगाल के किसी मुख्यमंत्री के मन में यह विचार तक नहीं आया कि गंगा पर क्रूज़ चलाया जाए, जबकि यह नदी पूरे वैभव के साथ शहर से होकर बहती है। इस प्राकृतिक संसाधन का कभी उपयोग नहीं किया गया। गंगा का विशाल जल बस चुपचाप बहता रहता है। लंदन में एक ऐसी नदी है, जिसका महत्व गंगा से कहीं कम है, लेकिन लंदन ने उस नदी को अपनी पहचान का अहम हिस्सा बना लिया है।

कलकत्ता भी अपनी नदी के सहारे पर्यटन का उत्सव शुरू कर सकता है। यहां अंतरराष्ट्रीय नौका प्रतियोगिताएं आयोजित हो सकती हैं, नदी क्रूज़ चलाए जा सकते हैं, जल खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है और गंगा किनारे अत्यंत उच्चस्तरीय आवासीय परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो सबसे अमीर भारतीयों की पसंद हो सकती हैं। कलकत्ता के पास खुद को अंतरराष्ट्रीय उच्चस्तरीय खेल आयोजनों का केन्द्र बनाने की क्षमता और संसाधन हैं। दुनिया भर में आपको लोग यूएस पोलो एसोसिएशन की टी-शर्ट पहने दिखाई देंगे। यह ब्रांड अरबों डॉलर का कारोबार करता है। लेकिन दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब कलकत्ता में है। कभी यहाँ का "पोलो सीज़न" शानदार हुआ करता था, जो अब लगभग समाप्त हो चुका है।

हमने अभी देखा कि भारतीय मूल के एक ब्रिटिश गोल्फर ने प्रतिष्ठित अमेरिकी पीजीए टूर्नामेंट जीता। कलकत्ता में कई ऐतिहासिक गोल्फ क्लब हैं, जिनमें से एक दुनिया का दूसरा सबसे पुराना माना जाता है। ये प्रतिष्ठित क्लब दूसरे देशों के क्लबों के साथ साझेदारी कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं।

इसी तरह घुड़दौड़ के क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। एक समय था जब ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य कलकत्ता रेसकोर्स में दौड़ देखने आते थे। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ भी अपनी यात्रा के दौरान वहां गई थीं। आरसीटीसी सिंगापुर या दुबई जैसे केन्द्रों के साथ साझेदारी कर आयोजन कर सकता है और रॉयल्टी कमा सकता है। आज, और आने वाले समय में केवल फुटबॉल या क्रिकेट ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। उच्च वर्ग के लोगों के लिए ये अन्य खेल भी बहुत आकर्षण रखते हैं। ऐसे आयोजन किसी स्थान को विशिष्ट पहचान दे सकते हैं।

एक तरह से ये खेल विरासतें औपनिवेशिक अतीत की निशानियां हैं। हमें औपनिवेशिक दौर के प्रति भावुक विरोध रखने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है कि हम इन अवशेषों का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। कलकत्ता के भीतर एक प्राकृतिक शाही भव्यता है, जो वर्षों की उपेक्षा, गंदगी और अव्यवस्था की परतों के नीचे दब गई है। इन्हें साफ कर पुरानी चमक वापस लाई जा सकती है। आखिर एक समय था, जब कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता था।

महलों का शहर कहलाने में कोई शर्म नहीं है। उन्हें सही ढंग से प्रस्तुत कीजिए और एक उज्ज्वल छवि बनाइए। ऐसा जीवंत शहर, जहां बाहर से आने वाला व्यक्ति उतरते ही सोचे - "क्या मैं यहां रह नहीं सकता?"

आज बंगाल को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रतिभाशाली लोगों और निवेश को आकर्षित करने की।

'सरकार के पास ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहमति जताते हुए कह रहे हैं कि जाति जनगणना से सामाजिक नीतियों का निर्माण अधिक सटीक होगा और ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी।

चर्चा के दौरान, अनेक हितधारकों ने जाति जनगणना का समर्थन किया है। वकीलों ने कहा है कि इससे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और नीति निर्माण में समाज की वास्तविक संरचना को पहचानने में मदद मिलेगी।

अदालत की टिप्पणियों के संदर्भ में, सरकारी प्रतिनिधियों ने पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की आवश्यकता स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में डेटा संग्रह की प्रक्रिया को सुधारने के उपाय पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इसकी समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि अगली सुनवाइयों में इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी जाए। इसके अलावा, सरकार पर जाति जनगणना कराने के अपने दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराने का दबाव भी है। कई लोग तर्क दे रहे हैं कि अपर्याप्त डेटा असमानताओं को बढ़ावा दे सकता है। अधिकारियों ने इस मुद्दे को संबोधित करने की प्रतिबद्धता जताई है और कहा कि जनगणना सभी समुदायों के लिए समान प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का दीर्घकालिक समाधान है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि कोर्ट का जाति जनगणना पर जोर केवल निष्पक्षता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा बनाने का प्रयास भी है, जिसमें सभी नागरिक सरकारी संसाधनों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें। यह दृष्टिकोण उन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, जो समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

जाति जनगणना के संभावित कार्यान्वयन से भारत में सामाजिक सेवाओं के भविष्य की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जैसे-जैसे विभिन्न राज्य जाति आधारित डेटा संग्रह शुरू करने पर चर्चा करेंगे, न्यायिक निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि स्पष्ट और सुपरिभाषित डेटा सभी स्तरों पर सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक जानकारीयुक्त और प्रभावी बना सकता है।

किसी भी संभावित जनगणना की तैयारी के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसले अंततः नीति निर्माण में जाति संबंधी मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए, इसका उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। कोर्ट ने सटीक जनगणना डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और जिम्मेदारी की अपील की है, ताकि पिछड़ी जातियों की वास्तविक परिस्थितियों को पहचाना और संबोधित किया जा सके।

जैसे-जैसे जाति जनगणना पर चर्चा आगे बढ़ती है, सार्वजनिक भागीदारी और उसकी वकालत के प्रयास यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि इस पहल से अल्पसंख्यक और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को वास्तविक लाभ मिले। न्यायपालिका द्वारा इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करना भारत की विविधतापूर्ण जनसंख्या को समझने और सेवा देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता को फिर से रेखांकित करता है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908